

उत्तरांचल शासन

ऊर्जा विभाग

संख्या: (356/04)/221/नौ-3-ऊ0/ज0वि0नीति/03

दिनांक: देहरादून: 28 जनवरी, 2004

अधिसूचना

उत्तरांचल राज्य में 100 मेगावाट से अधिक क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र की भागीदारी से विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति, जिसकी प्रति संलग्न है, को तत्काल प्रभाव से लागू करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

एस0 कृष्णन्

प्रमुख सचिव

पृ0स0 :- (356/04)/221/नौ-3-ऊ0/ज0वि0नीति/03/ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को जल विद्युत नीति की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— सचिव, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली।
- 2— सचिव, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार, लोधी रोड, नई दिल्ली।
- 3— संयुक्त सचिव, (हाईडिल) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार।
- 4— केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, पांचवा तल, कोर-3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7-इंस्टीटयुशन एरिया, लोधी रोड नई दिल्ली।
- 5— केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली।
- 6— प्रमुख सचिव-मा0 मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 7— समस्त मा0 मंत्रीगणों के निजी सचिवों को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
- 8— निजी सचिव-मा0 राज्य मंत्री, ऊर्जा को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 9— निजी सचिव-मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 10— निजी सचिव-अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 11— सचिव, विद्युत नियामक आयोग, उत्तरांचल, देहरादून।
- 12— समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 13— मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी एवं नैनीताल।
- 14— अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल जल विद्युत निगम/उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून।
- 15— निदेशक, उरेडा, देहरादून।
- 16— उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को नीति की हिन्दी व अंग्रेजी प्रति राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
- 17— सचिव, सूचना प्रौद्योगिक/NAIC को नीति के शासन की वैबसाइट में सम्मिलित करने हेतु। 100 MW तक की नीति की प्रति भी वैबसाइट में सम्मिलित करने हेतु।

आज्ञा से



(डा0एम0सी0जोशी)

अपर सचिव

100 मेगावाट से अधिक क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के पूंजीनिवेश सम्बन्धी नीति

1- क्षेत्र एवं उद्देश्य

उत्तरांचल राज्य में लगभग 15000 मेगावाट की चिन्हित जल-विद्युत क्षमता विद्यमान है। इस के विरुद्ध लगभग 1100 मेगावाट की उत्पादन क्षमता पूर्व ही स्थापित की जा चुकी है। लगभग कुल 7900 मेगावाट की क्षमता की परियोजनायें विकसित हो रही हैं।

उत्तरांचल सरकार ने इस तथ्य को स्वीकारते हुये कि प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास एवं देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश की जल विद्युत क्षमता का अधिकाधिक दोहन न्यूनतम समय में किये जाने की आवश्यकता है, इस क्षेत्र को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप, केन्द्रीय, राज्य एवं निजी सभी क्षेत्रों में प्रदेश में कई जल विद्युत परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं। 0 मेगावाट से 100 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं में निजी पूंजीनिवेश हेतु दिनांक: 19.10.2002 को नीति घोषित की जा चुकी है। प्रदेश में ऐसे कई स्थल हैं, जहां पर 100 मेगावाट क्षमता से अधिक की जल विद्युत परियोजनायें स्थापित की जा सकती हैं। ऐसी परियोजनाओं के विकास हेतु निजी पूंजीनिवेश को आकर्षित करने एवं दिनांक: 19.10.2002 को घोषित नीति के अनुक्रम में उत्तरांचल शासन ने वर्तमान नीति को घोषित करने का निर्णय लिया है।

2- सहभागिता एवं परिचालन अवधि:

- 2.1 यह नीति राजाज्ञा द्वारा निर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। 100 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनायें, जो उत्तरांचल सरकार द्वारा निजी पूंजीनिवेश हेतु प्रदिष्ट की जायेंगी इस नीति के अन्तर्गत पात्र होगी और अपनी सम्पूर्ण अवधि में इस नीति से शासित होगी।
- 2.2 उत्तरांचल सरकार, चिन्हित कार्यस्थलों के विकास हेतु, निजी क्षेत्र के पूंजीनिवेश-प्रस्ताव को आमंत्रित करेगी। चिन्हित कार्यस्थलों से सम्बन्धित परियोजनाओं की प्रारम्भिक रूपरेखा प्रतिस्पर्धात्मक निविदा की कार्यवाही से पूर्व निवेशकर्ता को उपलब्ध कराये जायेंगी।

3- पूर्व अर्हता निर्धारण

समय-समय पर उत्तरांचल सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये प्रत्येक चिन्हित कार्यस्थल हेतु निविदादाताओं का पूर्व अर्हता निर्धारण किया जायेगा, जो उनके पूर्व-अनुभव तथा वित्तीय एवं तकनीकी क्षमता पर आधारित होगा। पूर्व अर्हता निर्धारण में योग्य पाये गये आवेदक प्रतिस्पर्धात्मक निविदा देने के लिये पात्र होंगे। पूर्व-अर्हता हेतु हर तरह की क्षमता का आंकलन किया जायेगा। पूर्व अर्हता के आंकलन हेतु मार्गदर्शन सिद्धान्त एवं विभिन्न क्षमताओं के लिये उत्तीर्णांक की घोषणा पूर्व अर्हता निर्धारण हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करते समय की जायेगी।

4- आवंटन की प्रक्रिया

- 4.1 उत्तरांचल सरकार द्वारा चिन्हित परियोजनायें अन्तर्राष्ट्रीय निविदा हेतु विज्ञापित की जायेगी। समस्त इच्छुक आवेदक पूर्व प्रस्तर-3 के अधीन पूर्व-अर्हताओं के अधीन होंगे।
- 4.2 आवेदन पत्रों के साथ उत्तरांचल सरकार अथवा उसकी नामित संस्था के पक्ष में देय रु0 5.00 लाख (रुपये पांच लाख) का ड्राफ्ट संलग्न किया जायेगा, जो वापस नहीं होगा।
- 4.3 निविदायें राज्य सरकार को अपफ्रन्ट देय न्यूनतम प्रीमियम, जो प्रति परियोजना रु0 5.00 (पांच) करोड़, होगी, के आधार पर आमंत्रित की जायेगी। परियोजनायें अपफ्रन्ट न्यूनतम प्रीमियम से ऊपर अधिकतम बोली वाले निविदादाताओं को आवंटित की जायेगी। न्यूनतम प्रीमियम से कम की निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.4 परियोजनायें उच्चतम निविदा बोली देने वाले को आवंटित की जायेगी। सफल निविदादाताओं से न्यूनतम प्रीमियम राशि एवं इस राशि के ऊपर बोली गई निविदित धनराशि का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत जमा करने की अपेक्षा की जायेगी। न्यूनतम प्रीमियम के ऊपर निविदा की शेष 50 (पचास) प्रतिशत राशि के स्थान पर निविदादाता को बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है, जो वास्तविक अथवा निर्धारित वित्तीय प्रबन्धन, जो भी पहले हो, के समय कैश की जा सकेगी।
- 4.5 यदि दो या अधिक समरूप निविदायें, जो किसी परियोजना विशेष के लिये सर्वोत्तम निविदा के रूप में आविर्भावित हों, प्राप्त होती हैं तो आवंटन समरूप निविदादाताओं के मध्य चयन पूर्व-अर्हता आंकलन में प्राप्त औसत अंको के आधार पर किया जायेगा।

- 4.6 आवंटनोपरान्त आवंटी/विकासकर्ता द्वारा निश्चित समयावधि के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) तैयार करने हेतु उत्तरांचल शासन के साथ नियत समय (तीन माह) में परियोजना विकास अनुबन्ध हस्ताक्षर करना होगा। डी०पी०आर० की उत्तरांचल सरकार द्वारा स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त आवंटी/विकासकर्ता उत्तरांचल सरकार के साथ एक क्रियान्वयन-अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगा, जिसमें परियोजना के लिये आवश्यक विधिक/प्रशासनिक/तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने, वित्तीय प्रबन्धन, निर्माण/उत्पादन आरम्भ करने आदि की समय-सारिणी सम्मिलित होगी।
- 4.7 विश्वसनीय डी०पी०आर० (Viable DPR) न बनने अथवा विधिक/प्रशासनिक/तकनीकी अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में परियोजना उत्तरांचल शासन द्वारा उक्तानुसार नियत अवधि उपरान्त राज्य सरकार को वापस हो जायेगी तथा आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। ऐसी दशा में आवंटी को कोई प्रतिकर अनुमन्य नहीं होगा तथा उसके द्वारा भुगतान की गई राशि राज्य सरकार में जब्त हो जायेगी।

5- परियोजना आवंटन की शर्तें

- 5.1 परियोजनायें 45 वर्षों की प्रारम्भिक अवधि के लिये आवंटित की जायेंगी। अग्रेत्तर समयावधि (यों) में वृद्धि आपस में निर्धारित शर्तों के अनुसार की जा सकेंगी। प्रारम्भिक अवधि अथवा बढ़ायी गयी अवधि, जैसी भी स्थिति हो, की समाप्ति पर परियोजनायें उत्तरांचल सरकार को वापिस प्राप्त हो जायेगी।
- 5.2 परियोजना की परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण विकासकर्ता द्वारा इस प्रकार किया जायेगा ताकि निर्धारित क्षमता के अनुसार परियोजना की अवशेष आयु किसी भी समय आगे तीस वर्षों हेतु सुनिश्चित रह सके। इस हेतु परिचालन के दसवें, बीसवें, तीसवें एवं चालीसवें वर्ष तथा आवंटन के अन्तिम वर्ष में उत्तरांचल शासन अथवा इसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारियों में से किसी एक संस्था द्वारा परियोजना का यह सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्यतः निरीक्षण किया जायेगा कि परियोजना-परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता एवं संयन्त्र की अवशेष आयु सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार किया जा रहा है।
- 5.3 यदि ऐसे निरीक्षण में पाया जाय कि संयन्त्र क्षमता और/अथवा आयु का अपर्याप्त अनुरक्षण के अभाव में हास हो रहा है तो उत्तरांचल सरकार को सुविधाधारक से उपचारात्मक साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

यदि सुविधाधारक अपेक्षाओं के अनुपालन में असफल रहता है तो उत्तरांचल सरकार को निम्नानुसार आंगणित क्षतिपूर्ति का भुगतान कर सुविधा समाप्त करने का अधिकार होगा। समापन क्षतिपूर्ति लागत अंशधारकों के आगामी दस वर्षों के लाभांश के नियत मौद्रिक प्रवाह अथवा छूट की अवधि, जो भी कम हो, के आंकलन पर आधारित होगी। मौद्रिक प्रवाह एवं छूट की दर - दोनों का ही आंकलन उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, जो विनिर्दिष्ट मानकों के स्तर तक लाने हेतु परियोजना परिसम्पत्तियों को आलोकित करने, पुनरोद्धारित करने एवं मरम्मत करने आदि पर होने वाले व्यय का भी संज्ञान लेगा।

5.4 समस्त परियोजनायें उत्तरांचल शासन की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का अनुसरण करेंगी।

6- ऊर्जा का विक्रय

परियोजना के विकासकर्ता को विद्युत प्रदेश से बाहर बिक्री करने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रदेश की कोई भी संस्था विद्युत कय करने की गारन्टी नहीं देगी। यदि किसी समय प्रदेश को अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता हो तो प्रदेश की सम्बन्धित संस्था परियोजना से विकासकर्ता और सम्बन्धित संस्था के मध्य आपसी समझौते से निर्धारित की जाने वाले नियमों एवं शर्तों पर विद्युत कय कर सकेंगे।

7- स्वत्व-शुल्क

7.1 उत्पादित विद्युत का बारह (12) प्रतिशत अंश राज्य को परियोजना की सम्पूर्ण परिचालन अवधि में निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। यह निःशुल्क विद्युत, आवंटन के समय प्राप्त धनराशि के अतिरिक्त होगी।

7.2 क्रियान्वयन अनुबन्ध में निहित विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व परियोजना पूर्ण करने पर विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन अनुमन्य होगा। यह प्रोत्साहन प्रत्येक एक वर्ष पूर्व पूर्णता पर 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत में एक (1) प्रतिशत प्रतिवर्ष की छूट के आधार पर तय किया जायेगा। इसी प्रकार पूर्णता में विलम्ब पर 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत के अतिरिक्त अनिवार्यतः एक(1) प्रतिशत प्रतिवर्ष का दण्डात्मक स्वत्व-शुल्क विलम्ब के प्रत्येक वर्ष के लिये लिया जायेगा। तथापि यदि पूर्णता में विलम्ब तीन वर्ष से अधिक होता है तो परियोजना का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

7.3 इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी विधि के अनुरूप प्रभावी होगी।

8- विद्युत निकासी

विकासकर्ता अपनी निजी निकासी प्रणाली निर्मित कर सकता है अथवा प्रदेश के पारेषण/वितरण निगम/भारत के पावर ग्रिड कारपोरेशन के माध्यम से निर्मित करा सकता है। यदि निकासी प्रणाली को राज्य के उपक्रम के द्वारा निर्मित कराया जाता है तो यह एक व्यावसायिक उपक्रम के रूप में विकसित किया जायेगा। इस स्थिति में अथवा विद्युत निकासी प्रणाली के उपयोग की स्थिति में, विकासकर्ता द्वारा प्रदेश के निगम/केन्द्रीय संस्था को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित व्हीलिंग चार्ज का भुगतान करना होगा।

9- विस्थापन/पुनर्वास

परियोजना क्षेत्र के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिये परियोजना के विकासकर्ता उत्तरदायी होंगे तथा इसकी लागत परियोजना-लागत में सम्मिलित होगी। राज्य सरकार विकासकर्ता को पुनर्वास एवं विस्थापन की योजना के क्रियान्वयन में आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

10- आधारभूत सुविधायें

परियोजना के निर्माण/विकास के लिये आवश्यक आधारभूत सुविधायें परियोजना-लागत की अंश होगी और विकासकर्ता द्वारा विकसित की जायेंगी।

11- राज्य सरकार से प्रोत्साहन

राज्य सरकार द्वारा परियोजना की निर्माण अवधि में निर्माण सामग्री, विद्युत उत्पादन/पारेषण संयन्त्रों पर कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जायेगा।

12— विविध

- 12.1 राज्य सरकार अपेक्षित अनुमोदनों/स्वीकृतियों एवं अन्य सम्बन्धित मामलों में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। राज्य सरकार एवं इसकी सम्बन्धित संस्थाओं से स्वीकृतियां/अनुमोदनों के लिये एक अधिकार-प्राप्त समिति अथवा एक नोडल संस्था नामित की जायेगी।
- 12.2 यदि परियोजना से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट/आंकड़े आदि राज्य सरकार के विभागों/निगमों द्वारा विकासकर्ता को उपलब्ध कराये जाते हैं तो इस प्रकार के अभिलेखों को तैयार करने में हुआ व्यय विकासकर्ता द्वारा भुगतान किया जायेगा।

—

✓

POLICY ON PRIVATE SECTOR INVESTMENT IN HYDROPOWER PROJECT ABOVE 100 MW CAPACITY.

1. SCOPE AND OBJECTIVES:

The State of Uttaranchal has an identified Hydro power potential of about 15000 MW. Out of this generating capacities of about 1100 MW have already been established. Projects totaling to a capacity of about 7900 MW are in the pipeline.

The Government of Uttaranchal (GOU), recognising the fact that the hydro power potential of the state needs to be harnessed to the maximum in the shortest possible time for the economic development of the state and for meeting the energy demand of the country, has accorded top priority to this sector. As a result thereof, a number of Projects in Central sector, State sector and Private sector are being set up in the State. A policy for private sector investment in the Hydropower projects ranging for 0 to 100 MW has already been announced on 19-10-2002. There are a number of sites where hydropower project of the capacities larger than 100 MWs can be established. To attract private investment for the development of such projects and as a sequel to the policy of 19-10-2002, the Government of Uttaranchal has decided to announce this policy.

2. PARTICIATION AND OPERATIVE PERIOD:

- 2.1 This policy shall be in operation from the date of its publication as notified by Government order. Projects, above the capacity of more than 100 MW offered by GOU for private investment will be eligible under this policy and will be governed by this policy for their entire duration.
- 2.2 The GOU will invite proposals from private sector investors for development of identified sites. The preliminary project profiles of the identified sites will be made available to the investors before the process of competitive bidding.

3. PRE-QUALIFICATION:

For each identified site, which will be notified by the GOU from time to time, there shall be a pre-qualification selection of the bidders based on their past experience and financial and technical capacity. The applicants qualifying in the pre-qualification selection will be eligible for competitive bidding. Each attribute set for pre-qualification will be evaluated. Guidelines for evaluation and the passing score on attribute required for pre-qualification shall be specified at the time of inviting proposal for pre qualification.

4. PROCESS OF ALLOTMENT

- 4.1 Project identified by the Government of Uttarakhand shall be advertised for inviting international bids. All interested parties will be subject to pre qualification as provided in Para-3, above.
- 4.2 Application should be accompanied by a non-refundable draft of Rs.5.00 lacs, payable to GOU or its designated agency.
- 4.3 Bids shall be invited over a minimum premium, payable upfront to the Government of Uttarakhand, at the rate of Rs. 5 (Five) Crores per project. Project will be allotted to bidders making the highest bid over and above the upfront minimum premium. Bids below the minimum premium shall not be considered.
- 4.4 Project will be allotted to the highest bidders. The successful bidder shall be required to deposit the minimum premium and 50% of the bid amount in excess of the minimum premium within the period fixed by the Government in this behalf. For the remaining fifty percent (50%) of the bid amount in excess of the minimum premium, the bidder may be permitted to provide a bank guarantee encashable at the time of actual or scheduled financial closure, whichever is earlier.
- 4.5 If there are two or more identical bids which emerge as the best bids for any project, allotment will be made on the basis of the average score obtained in valuation of the pre qualification among the identical bidders.
- 4.6 After the allotment the allottee/developer shall have to sign a project development agreement with GOU within the period fixed by GOU (Three month) for preparation of detailed project report (DPR) within a prescribed time frame. After the DPR is accepted/approved by GOU, the allottee/ developer shall have to sign an implementation agreement with GOU which shall *interalia* include time schedule for getting necessary legal/administrative/technical approvals, financial closure, construction/commissioning etc. of the project.
- 4.7 In the events of inability of preparing a viable DPR or getting legal/administrative/technical approvals after the completion of the above mentioned fixed period the project will revert back to GOU and the allotment shall be treated cancelled automatically. In such a case no compensation will be payable to the allottee and the amount paid by allottee shall vest in the GOU.

5. TERMS OF ALLOTMENT OF THE PROJECT

- 5.1 project will be allotted for an initial period of 45 years. Extension for further period (s) can be given on the terms & conditions to be decided mutually. After the expiry of the initial period or the extended period, as the case may be, the project will revert back to the Government of Uttaranchal.
- 5.2 The project assets would be maintained by the developer in a condition that would ensure a residual life of the project at the rated capacity for at least 30 years at any point of time. During the 10th, 20th, 30th, and 40th years of operations as well as during the last year of allotment, Govt. of Uttaranchal or one of its appointed agencies would carry out a mandatory inspection of the project to ensure that the project assets are maintained to the required standards to ensure the specified generation capability and residual life of the plants.
- 5.3 If such inspections find that the plant capacity and/or life are being undermined by inadequate maintenance, the GOUA would be entitled to seek remedial measures from the concessionaire.
- If the concessionaire fails to comply with the requirements, the GOUA would have the right to terminate the concession by payment of compensation to be computed as follows. The termination compensation value would be based on estimated net cash flows to equity shareholders for the next ten years or residual period of concession, whichever is lesser, discounted at a suitable rate. Both the estimate of cash flows as well as the discount rate would be approved by the Uttaranchal Electricity Regulatory Commission (UERC) which will also factor the costs of refurbishment, renovation, repairs, etc. required to bring the project assets to the standards specified.
- 5.4 All projects would need to conform to the R&R policy of the GOUA,

6. SALE OF POWER

The developer of the project will have the right to sell the power outside the State. No agency of the State will guarantee purchase of power. If anytime the state requires additional power, the concerned organisation of the State, may purchase electricity from the project on terms and conditions to be decided mutually by the developer and the concerned agency.

7. **ROYALTY**

- 7.1 Twelve percent (12%) of electricity generated shall be made available free of cost to the State during the entire life of the Project. This free power will be in addition to the amounts received at the time of allotment.
- 7.2 Completion of the project prior to the scheduled date as contained in the implementation agreement will attract incentive to the developer. This incentive will be decided on the basis of a rebate of one percent (1%) per year on the 12% free power for each year of earlier completion. Likewise delay in completion will also entail penalty of one percent (1%) for one year over and above the 12% free power for each year of delay. However, in case the delay in completion is for more than three years the allotment of the Project may be cancelled.
- 7.3 Electricity duty shall be applicable as per law.

8. **POWER EVACUATION:**

The developer may build his own evacuation system or get the same constructed through the Transmission/Distribution Corporation of the State/Power Grid Corporation of India. If the evacuation system is constructed by the undertaking of the State, the same will be developed as a commercial venture. In this case or in the case of utilization of existing evacuation system, wheeling charges, as determined by the Central Electricity Regulatory Commission or Uttaranchal Electricity Regulatory Commission, will be payable by the developer to the State Corporations/Central utility.

9. **DISPLACEMENT/REHABILITATION:**

The developer of the project shall be liable for the rehabilitation of the displaced persons from the project area and the cost of the same shall be included in the project cost. The State Government will provide necessary assistance to the developer in implementation of R&R Plan.

10. **INFRASTRUCTURE:**

The necessary infrastructure for the construction/development of the project will be part of the project cost and will be developed by the developer.

11. INCENTIVE FROM STATE GOVERNMENT:

No entry tax will be levied by the State Govt. on building material, power generation/transmission equipment during construction of the project.

12. OTHERS:

- 12.1 State Govt. will provide necessary assistance for required approvals/clearances and other related matters. For clearances/approvals from the State Government and its concerned agencies, an empowered committee or a nodal agency will be nominated.
- 12.2 If any report/data etc. relating to the project are made available to the developer by the State Government Department/Corporations, the cost incurred in preparation of such documents will be paid by the developer.

--*--